प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
26.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1100 बजे

प्रधानमंत्री – वर्ल्ड फूड इंडिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक निवेशक, विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र के निवेशक भारत की तरफ बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू मांग भारत को प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण और निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाला राष्ट्र बनाती है। 21वीं सदी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न हुई भारत ने निरंतर सकारात्मक भूमिका निभाई है।

जो जो चौलेंज दुनिया के सामने आए हैं भारत में आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे किसने हमारे पशुपालकों को हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का समर्थ निरंतर बढ़ रहा है बीते दशक में हमारे फूड ग्रेड प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है

फूड इंडिया कार्यक्रम में भाग ले रहे सोलन जिला के किसान हिमांशु शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपने खेतों में उगाये गए फलों, ड्राई फ्रूट और सब्जियों के प्रदर्शन के लिए अवसर मिलने पर वर्ल्ड फूड इंडिया का आभार प्रकट किया।

बाईट––हिमांशु वर्ल्ड

हमारी सारी ही प्रोडक्ट नेचुरल है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है यह प्योर ऑर्गेनिक है जिसे हमारे छोटे–छोटे फार्मर करते हैं मैं भारत सरकार का और मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें यह मौका दिया ताकि हम भी अपने फार्म की बात आगे रख सके और यह बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म

अनुदान

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत असंबद्ध अनुदानों की पहली किस्त के रूप में 67 करोड़ 95 लाख रुपये जारी किए है। इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति ,घरेलू कचरे का प्रबंधन व उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण कार्य किये जायेगे।

जीएसटी सुधार

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं जो 22 सितम्बर से लागू हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पांच प्रतिशत, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर संरचना के स्थान पर अब पांच और 18 प्रतिशत कर संरचना लागू की है। माल और वस्तुओं की व्यापक रेंज पर कर की दर घटने से नागरिकों को अत्यधिक राहत मिली है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधारों को मंजूरी देते हुए, इसे आम लोगों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिक सरल और लाभकारी बना दिया है। अब तक लागू होने वाले पांच, बारह, अठारह और अठाईस प्रतिशत की चार स्तरीय संरचना को घटाकर केवल पांच और अठारह प्रतिशत की दो स्तरीय संरचना कर दी गई है। इसके साथ ही तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे चुनिंदा वस्तुओं पर चालीस प्रतिशत का अतिरिक्त स्लैब लगाया गया है। परिषद का कहना है कि दरों का यह युक्ति–संगतीकरण आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य चालकों को राहत देगा। नए ढांचे के तहत कई आवश्यक खाद्य पदार्थ, जैसे अति उच्च तापमान वाला दूध, छेना, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड और चपाती को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की जरूरतें और सस्ती होंगी। कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों जैसे उपकरणों पर जीएसटी बारह से घटाकर पांच कर दिया गया है। वहीं, तीन सौ पच्चास सीसी तक के दो पहिया वाहनों पर जीएसटी अठाईस से घटाकर अठारहा कर दिया गया है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग श्रमिकों को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली निवासी अभय प्रताप ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ष्मैं अभी अपने लिए जीएसटी दरों में कटौती होने के कारण, जो अठाईस से अठारहा हुआ है, इसलिए बाइक लेने जा रहा हूं इस दिवाली में। सरकार का मैं तहे दिल से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।ष नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते है दोपहर 3 बजे। नमस्कार.....

———————————